



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, २७ सितम्बर, १९९५/ ५ आश्विन, १९१७

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-२, २७ सितम्बर, १९९५

सं १-४/९५ वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, १९७३ के नियम १३५ के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत (उत्पादन वितरण) विधेयक, १९९५ (१९९५ का विधेयक संख्यांक ५)

जो दिनांक 27 सितम्बर, 1995 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो गया है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

1995 का विधेयक संख्यांक 5.

हिमाचल प्रदेश विद्युत (उत्पादन कराधान) विधेयक, 1995

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन पर कर उद्गृहीत करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न-लिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इन अधिनियम वा संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत (उत्पादन कराधान) अधिनियम, 1995 है । संक्षिप्त नाम,
विस्तार
और
प्रारम्भ ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है ।
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,— परिभाषाएं

1910 का 9

- (क) "विद्युत निरीक्षक" से विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 36 के अधीन नियुक्त मुख्य विद्युत निरीक्षक, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ;
- (ख) "सक्षम प्राधिकारी" से इस अधिनियम की धारा 7 के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है ;
- (ग) "ऊर्जा" से जल विद्युत ऊर्जा अभिप्रेत है ;
- (घ) "मीटर" से ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त साधन या यन्त्र अभिप्रेत है ;
- (ङ) "विहित" से इन अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
- (च) "कर" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्गृहीत कर अभिप्रेत है ; और
- (छ) "यूनिट" से ऊर्जा के सम्बन्ध में किलोवाट-घंटा अभिप्रेत हैं ।

3. (1) हिमाचल प्रदेश राज्य में उत्पादित ऊर्जा पर, "विद्युत उत्पादन कर" के नाम से ज्ञात कर, ऊर्जा की प्रति यूनिट पर 10 पैसे की दर से विहित रीति में उद्गृहीत किया जाएगा और सरकार को संदत्त किया जाएगा ।

ऊर्जा उत्पादन पर कर का उद्ग्रहण ।

(2) उप-धारा (1) की कोई भी बात ऊर्जा के उत्पादन के लिए उत्पादन केंद्रों द्वारा उपभुक्त ऊर्जा पर लागू नहीं होगी ।

(3) इस धारा के अधीन कर की संगणना करने के लिए, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् मीटर के प्रथम वाचन की तारीख के पश्चात् से प्रारम्भ होने वाले मीटरों द्वारा दर्शाए गए ऊर्जा उत्पादन को हिसाब में लिया जाएगा और एक मास का उत्पादन गणना का आधार होगा।

कर संग्रहण और सहाय। 4. इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कर विद्युत निरीक्षण या किसी अन्य अधिकारी द्वारा जिसे इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, ऊर्जा का उत्पादन करने वाले व्यक्तियों से, संगृहीत किया जाएगा और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा।

अभिलेख और विवरणियाँ। 5. (1) यदि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निर्देश दे, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो ऊर्जा का उत्पादन करता है और इस अधिनियम के अधीन कर के संदाय के लिए दायी है, ऐसे अभिलेख ऐसे प्रारूप और रीति में रखेगा जो विहित की जाए, जिसमें निम्नलिखित दर्शाया जाएगा —

- (क) उत्पादित या उत्पन्न की गई ऊर्जा की यूनिटें;
- (ख) उन पर संदेय कर की रकम;
- (ग) इस अधिनियम के अधीन संदत्त कर की रकम; और
- (घ) ऐसी अन्य विनिर्दिष्टियाँ जो विहित की जाएँ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अभिलेख रखने के लिए निर्दिष्ट, ऐसी विवरणियाँ, ऐसे प्रारूप और रीति में और राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जैसा कि विहित किया जाए।

निरीक्षण अधिकारी। 6. (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 5 के अधीन रखे गए अभिलेख के निरीक्षण के लिए निरीक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकती।

(2) निरीक्षण अधिकारी इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी विहित की जाएँ।

(3) इस धारा के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक निरीक्षण अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ में लॉफ़ सेवक समझा जाएगा।

कुछ मामलों में शामिल कर या संदाय लिया जाना। 7. (1) यदि सक्षम प्राधिकारी की राय में ऊर्जा का उत्पादन करने वाला व्यक्ति चाहे मिथ्या अभिलेख रखकर, मिथ्या विवरणियाँ प्रस्तुत करके, उत्पादित ऊर्जा को छिपा कर या किसी अन्य साधन द्वारा कर के संदाय का अपवर्चन करता है या अपवर्चन करने का प्रयास करता है, तो ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त शास्ति के रूप में कर की राशि के चार गुणा से अनधिक ऐसी रकम का संदाय करेगा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाए:

परन्तु इ। उप-धारा के अधीन कोई कार्रवाई ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान किए बिना नहीं की जाएगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसे प्राधिकारी को, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी फीन के संदाय पर, जो विहित की जाए, की जाएगी।

(3) उप-धारा (2) के अधीन अपील में पारित कोई आदेश अन्तिम और आबद्धकर होगा।

(4) इस धारा के अधीन शास्ति के संदाय के लिए दिया गया आदेश इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए संस्थित या संस्थित किए जाने वाले किसी अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

8. इस अधिनियम के अधीन कोई कर या धारा 7 के अधीन अधिरोधित शास्ति कर की ऊर्जा उत्पादित करने वाले व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को अमदत रहती है, भू-राजस्व वसूली। की बाधा के रूप में वसूली होगी।

9. यदि कोई व्यक्ति,—

शास्तियां।

(क) जिसने धारा 5 के अधीन अभिलेख रखना या विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, उसे विहित प्ररूप या रीति में रखने या प्रस्तुत करने में असफल रहता है या ऐसी विवरणी प्रस्तुत करता है जो मिथ्या है; या

(ख) धारा 6 के अधीन नियुक्त किसी निरीक्षण अधिकारी को इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में साधन बाधा पहुंचाता है; या

(ग) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी अन्य उपबन्ध का उल्लंघन करता है, तो वह, दंडसिद्धि पर, एक हजार रुपए से अनधिक जुर्माने का दायी होगा।

10. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा 3 के अधीन उद्गृहीत कर की दरों को पुनरीक्षित कर भेगी; किन्तु ऐसी कर दरें भारत के राष्ट्रपति की पूर्व मंमति के बिना बढ़ाई नहीं जाएंगी।

कर की दर का पुनरीक्षण करने की शक्ति।

11. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने लिए नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे,—

(क) धारा 3 के अधीन कर के संदाय की रीति;

(ख) विद्युत निरीक्षण, हिमाचल प्रदेश द्वारा कर के संग्रहण और राज्य सरकार को संदाय की रीति;

(ग) ऊर्जा का उत्पादन करने वाले व्यक्तियों द्वारा कर के संदाय का समय और रीति;

(घ) निरीक्षण अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और पालन किए जाने वाले कर्तव्य; और

(ङ) कोई अन्य विषय, जिसके लिए राज्य सरकार की राय में, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए करने आवश्यक हैं।

(3) इस अधिनियम को अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् मध्याह्नीय विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल भिन्नकर कीमत से अंशूल अर्वाध के लिए रखा जाएगा। यह अर्वाध एक सत्र में या दो या अधिक अनुवर्षों में गतों में पूरी हो सकेगी। यदि उक्त सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है, या पूर्वोक्त सत्रों के अवधान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करती है, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवधान से पूर्व विधान सभा यह निर्णय करती है कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रधान हो जाएगा। किन्तु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रधान होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की निष्प्रभावता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विभिन्न विकासोत्तमक कार्यक्रमों के शीघ्र निष्पादन के लिए आवश्यक अतिरिक्त संग्रामों के सभा में, हमारे विकासोत्तमक क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भाव्य है। इसलिए अतिरिक्त संग्रामों को संचालित करने के लिए राज्य में विद्यमान ऊर्जा के उत्पन्न पर कर उद्गृहीत करने का प्रस्ताव है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

बीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
27 सितम्बर, 1995.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 3 के अधीन प्रस्तावित कर से प्रतिवर्ष लगभग 153 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। यद्यपि कर विद्युत निरीक्षणालय के माध्यम से वसूल लिया जाना है, तथापि उक्त निरीक्षणालय को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त फर्मचारीबृन्द और उपकरणों पर 4 लाख रुपए का अनावर्ती तथा एक लाख रुपए का आवर्ती व्यय उपगत करना पड़ेगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 11 उसमें परिगणित विषयों और अन्य विषयों के बारे में, जिसके लिए विधेयक के उपबन्धों को प्रभावी करने के प्रयोजन से उपबन्ध करना आवश्यक और समीचीन है, नियम बनाने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करता है। ये नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, विधान सभा को समक्ष रखे जाएंगे। यह प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिश

[बहुउद्देशीय और विद्युत विभाग नस्ति संख्या एम0पी0पी0सी0 (4)-1/92]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विद्युत (उत्पादन कराधान) विधेयक, 1995 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 5 of 1995.

THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (TAXATION ON GENERATION) BILL, 1995

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to levy tax on the generation of hydro-electric energy in Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Electricity (Taxation on Generation) Act, 1995.

Short title,
extent and
commence-
ment.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

Definitions

(a) "Electrical Inspector" means the Chief Electrical Inspector, Himachal Pradesh, appointed under section 36 of the Electricity Act, 1910;

(b) "competent authority" means the authority appointed by the State Government for the purposes of section 7 of this Act;

(c) "energy" means hydro-electric energy;

(d) "meter" means an appliance or apparatus used for measuring the energy;

(e) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(f) "tax" means the tax levied under section 3 of this Act; and

(g) "unit" in relation to the energy means Kilowatt-hour.

3. (1) There shall be levied and paid to the State Government on the energy generated in the State of Himachal Pradesh, a tax to be called the "Electricity generation tax" in the prescribed manner, at the rate of 10 paise per unit of energy.

Levy of
tax on
generation
of energy.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to the energy consumed at the generating stations for generation of energy.

(3) For the purpose of computing the tax under this section, the generation of energy shown by the meters starting after the first meter reading date after the commencement of this Act shall be taken into account and generation in a month shall form the basis of calculation.

Collection
and payment
of tax.

4. The tax levied under this Act, shall, in the prescribed manner, be collected from the persons generating energy by the Electrical Inspector or any other officer who may be authorised in this behalf and be paid to the State Government.

Records
and returns.

5. (1) If the State Government so directs by a general or a special order, every person, who generates energy and is liable to pay the tax under this Act, shall maintain such records in such form and manner as may be prescribed, showing—

- (a) the units of energy generated or produced;
- (b) the amount of tax payable thereon;
- (c) the amount of tax paid under this Act; and
- (d) such other particulars as may be prescribed.

(2) Every person who has been directed under sub-section (1) to maintain records shall submit such returns, in such form and manner, and to such officer of the State Government, as may be prescribed.

Inspecting
Officers.

6. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint Inspecting Officers to inspect records maintained under section 5.

(2) The Inspecting Officers shall perform such duties and exercise such powers as may be prescribed for the purposes of carrying into effect the provisions of this Act and the rules made thereunder.

(3) Every Inspecting Officer appointed under this section shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

Penal tax
to be paid
in certain
cases.

7. (1) If in the opinion of the competent authority the person generating energy evades or attempts to evade the payment of tax, whether by maintaining false records, submitting false returns, concealing the energy generated or by any other means such person shall pay by way of penalty in addition to the tax payable under this Act, a sum not exceeding four times the amount of the tax, to be determined by the competent authority:

Provided that no action under this sub-section shall be taken without affording a reasonable opportunity of being heard to such a person.

(2) An appeal shall lie against an order passed under sub-section (1) to such authority, within such period and on payment of such fees, as may be prescribed.

(3) An order passed on appeal under sub-section (2) shall be final and binding.

(4) An order for the payment of any penalty made under this section shall be without prejudice to any prosecution instituted or which may be instituted for an offence under this Act.

Recovery
of Tax.

8. Any tax under this Act or penalty imposed under section 7 which remains unpaid by a person generating energy to the State Government, shall be recoverable as an arrear of land revenue.

9. If any person,—

Penalties

- (a) required by section 5 to keep records or to submit returns fails to keep or submit the same in the prescribed form or manner or submits a return which is false; or
- (b) intentionally obstructs an Inspecting Officer appointed under section 6 in the exercise of his powers and duties under this Act and the rules made thereunder; or
- (c) contravenes any other provision of this Act or the rules made thereunder,

he shall be liable on conviction, to a fine not exceeding one thousand rupees.

10. The State Government may, by notification, revise the rates of tax levied under section 3; provided that such rates of tax shall not be enhanced without the previous consent of the President of India.

Power to revise the rate of tax.

11. (1) The State Government may, by notification, make rules for the purposes of carrying into effect the provisions of this Act.

Power to make rules.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for,—

- (a) the manner of payment of the tax under section 3;
- (b) the manner of collection and payment of tax to the State Government by the Electrical Inspector, Himachal Pradesh;
- (c) the time and manner of payment of the tax by the persons generating energy;
- (d) the powers and duties to be exercised and performed by Inspecting Officers; and
- (e) any other matter for which, in the opinion of the State Government, rules are necessary for giving effect to the provisions of this Act.

(3) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the sessions aforesaid, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the absence of additional resources, necessary for speedy execution of various development programmes, our developmental activities are likely to be adversely affected. Thus, in order to mobilise additional resources, it has been proposed to levy a tax on the generation of the hydro-electric energy in this State.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objects.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :

The 27th September-1995.

FINANCIAL MEMORANDUM

The tax proposed under clause 3 of the Bill will yield approximately an additional income of Rs. 153 crores annually. Though the tax is to be realised through the Electrical Inspectorate, yet a sum of Rs. 4 lakhs as non-recurring and Rs. 1 lakh as recurring expenditure has to be incurred to strengthen the said Inspectorate by additional staff and equipment.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 11 of this Bill empowers the State Government to make rules in respect of the matters enumerated therein and other matters for which provision is necessary and expedient for the purpose of giving effect to the provisions of the Bill. These rules, as soon as may be, after these are made, are to be laid before the Legislative Assembly. This delegation is essential and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[M.P.P. and Power Department file No. MPP-C(4)-1/92]

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Electricity (Taxation on Generation) Bill, 1995, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

